

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2685
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2021

भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन

2685. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक; श्री रविन्दर कुशवाहा; श्री सुब्रत पाठक; श्री रवि किशन; श्री बिद्युत बरन महतो; श्री चंद्रशेखर साहू; श्री श्रीरंग आप्पा बारणे; श्री राजेन्द्र धेड्या गावित; श्री सुधीर गुप्ता:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत नेट परियोजना के चरण-एक और चरण-दो के क्रियान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार क्या स्थिति है एवं महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित इसके अंतर्गत अभी तक शामिल ग्राम पंचायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) क्या सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है जिसके द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी एवं यदि हां, तो इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्यौरा क्या है
- (ग) चरण-एक और चरण-दो के अंतर्गत पृथक रूप से अभी तक आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों में उच्चगति वाले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अवसंरचना के साथ कितने ब्रॉडबैंड कनेक्शन कार्य कर रहे हैं और प्रदान किए गए हैं; और
- (ड.) क्या विशेष रूप से उपर्युक्त वर्णित राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वाई-फाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) भारतनेट परियोजना को महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश की लगभग सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु नेटवर्क सृजित करने के लिए चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारतनेट के चरण-I को तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) नामतः भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है तथा इस चरण का निष्पादन लगभग पूरा हो चुका है। भारतनेट चरण-II को मीडिया (ओएफसी, रेडियो और सैटेलाइट) के इष्टतम मिश्रित उपयोग द्वारा राज्य-आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र मॉडल और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) आधारित मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश में भारतनेट परियोजना के तहत सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) भारतनेट परियोजना को अगस्त 2021 तक पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन और विभिन्न सरकारों द्वारा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के चलते कार्य की गति प्रभावित हुई है जिससे इस समय-सीमा को अब आगे बढ़ा दिया गया है।

(ग) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी) द्वारा जारी की गई निधि का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार विवरण अनुबंध-11 में दिया गया है।

(घ) और (ड.) दिनांक 26.02.2021 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,54,096 ग्राम पंचायतों (ब्लॉक मुख्यालय सहित) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के भाग के रूप में, वाई-फाई या अन्य किसी उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की सभी ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है।

1.10 लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सेवाएं शुरू करने का कार्य सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विशेष उद्देश्य साधन) और 10,000 ग्राम पंचायतों के लिए यह कार्य राजस्थान सरकार/राज सीओएमपी इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) इत्यादि को सौंपा गया है।

भारत में वाई-फाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को लगभग 1.10 लाख ग्राम पंचायतें सौंपी गई हैं, यह 77,000 (लगभग) ग्राम पंचायतों में 5 सरकारी संस्थानों को फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच) कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, राज्य-आधारित मॉडल के तहत, राज्य भारतनेट नेटवर्क के उपयोग के लिए जिम्मेवार हैं।

दिनांक 26.02.2021 की स्थिति के अनुसार, 1,03,400 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं और महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश में भारतनेट पर 4,95,078 एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

लोक सभा के दिनांक 10.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2685 के उत्तर के भाग (क) के संदर्भ में अनुबंध भारतनेट का राज्य/संघ-शासित प्रदेश की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चरण-I में सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें (ब्लॉक मुख्यालय सहित)	चरण-II में सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें (ब्लॉक मुख्यालय सहित)
1	आंध्र प्रदेश	1680	27
2	अरुणाचल प्रदेश	88	533
3	अंडमान और निकोबार	8	0
4	असम	1627	0
5	बिहार	6003	2818
6	चंडीगढ़	13	0
7	छत्तीसगढ़	4112	3134
8	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	39	0
9	गुजरात	6372	7019
10	हरियाणा	6203	0
11	हिमाचल प्रदेश	252	118
12	लद्दाख	0	186
13	जम्मू एवं कश्मीर	393	595
14	झारखंड	2600	997
15	कर्नाटक	6247	0
16	केरल	1129	0
17	लक्षद्वीप	0	0
18	मध्य प्रदेश	12698	2251
19	महाराष्ट्र	15335	3619
20	मणिपुर	326	1095
21	मिजोरम	41	327
22	मेघालय	122	372

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	चरण-। में सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें (ब्लॉक मुख्यालय सहित)	चरण-।। में सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतें (ब्लॉक मुख्यालय सहित)
23	नागालैंड	127	92
24	ओडिशा	3952	1681
25	पुडुचेरी	101	0
26	पंजाब	8040	4755
27	राजस्थान	8937	30
28	सिक्किम	28	0
29	तमिलनाडु	0	0
30	तेलंगाना	2047	0
31	त्रिपुरा	595	137
32	उत्तर प्रदेश	28242	2987
33	उत्तराखंड	1536	0
34	पश्चिम बंगाल	2430	0
कुल		121323	32773

अनुबंध-II

लोक सभा के दिनांक 10.03.2021 के अतारांकित प्रश्न सं. 2685 के उत्तर के भाग (ग) के संदर्भ में अनुबंध भारतनेट हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा जारी की गई निधियों का राज्य/संघ-शासित प्रदेश वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ-शासित प्रदेश	चरण-। के लिए जारी निधि (रू. में)	चरण-।। के लिए जारी निधि (रू. में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	152184834	0
2	आंध्र प्रदेश	3009081475	2271280000

क्र.सं.	राज्य/संघ-शासित प्रदेश	चरण-I के लिए जारी निधि (रू. में)	चरण-II के लिए जारी निधि (रू. में)
3	अरुणाचल प्रदेश	455796430	0
4	असम	1627920812	0
5	बिहार	4702466090	4314800000
6	छत्तीसगढ़	5202892683	10087831700
7	गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	3821047516	17068140000
8	हरियाणा	3851661631	0
9	हिमाचल प्रदेश	824901953	272445540
10	जम्मू और कश्मीर	771127190	0
11	झारखंड	2593841277	2964300000
12	कर्नाटक	6545168327	0
13	केरल	597060814	0
14	लक्षद्वीप	1034134	0
15	मध्य प्रदेश	16628285906	31000000
16	महाराष्ट्र	16451738937	11215880000
17	मणिपुर	495044991	0
18	मेघालय	666137968	0
19	मिजोरम	341256527	0
20	नगालैंड	600672076	0
21	ओडिशा	4853921628	3048767000
22	पुदुचेरी	48606957	0
23	पंजाब	3757757151	4808500000
24	राजस्थान	9017997157	472000000
25	सिक्किम	152094963	2000000
26	तमिलनाडु	108055326	1500820000

क्र.सं.	राज्य/संघ-शासित प्रदेश	चरण-I के लिए जारी निधि (रू. में)	चरण-II के लिए जारी निधि (रू. में)
27	तेलंगाना	2139124557	3352780000
28	त्रिपुरा	732190895	0
29	उत्तर प्रदेश	13559531296	2800000000
30	उत्तराखंड	2479300282	27700000
31	पश्चिम बंगाल	3963543831	20998295
	कुल	110151445615	64259242535
	* जीपीओएन और ओएफसी	1277609848	0
	* बीएसएनएल के लिए किया गया तदर्थ भुगतान	0	39350000000
	टीसीआईएल	0	310729117
	बीएसएनएल -वीसेट	0	423800000
	बैंडविडथ	0	401200000
	कुल योग	111429055463	104744971652
